माइल थी । अब नहर में पानी की वजह से आबादी बढ़ गई है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी कहीं 10 हजार, कहीं 15 हजार और कहीं 25 हजार हो गई है, लेकिन 1971 की जनगणना के अनुसार कहीं पांच, कहीं पन्द्रह और कहीं सौ थी । क्या 1981 की जनगणना को ध्यान में रखते हुये उस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने पहले ही प्रश्न के उत्तर मे कहा है कि जो मौजूदा गाइडलाइन है, उस के संबंध में हम विचार कर रहे हैं और इस को रिव्यूह करने जा रहे हैं ।

Sarin Committee Report on Telecommunications

*24. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the reasons for inordinate delay in implementin gthe Sarin Committee recommendations regarding separation of Telecommunication Service from the Postal Service;

(b) whether a number of Social Organisations and the Trade Unions have sent representation in favour of and against the Sarin Committee recommendations.

(c) whether Government propose to accept the recommendations in parts or as a whole; and

(d) by what time a final decision is likely to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): (a) The recommendations regarding seperation of Telecom. service from Postal Service have far reaching implications and will have wide impact on the two services. All aspects have therefore to be examined and gone into in great detail and depth before ariving at final decisions. These recommendations are still under consideration of Government.

(b) No Social Organisation has made any written representation on the subject. According to written communication on record, the recognised Federations of Trade Unions have not opposed, in principle, the question of bifurcation.

(c) These recommendations are still under consideration of the Government.

(d) The intention is to arrive at a final decision as early as possible.

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ऐसा ही गोलमाल जवाब दिया है जैसे कि यह पता नहीं होता कि नारी विच साड़ी है या साड़ी विच नारी है । . . . (**व्यवधान**)

Mr. Speaker: Not allowed.

श्री आर० एन० राकेश : बेहरहाल ड्यू है, तो डिलिवरी तो होगी ही । . . . (**व्यवधान**) . . . इसमें हम सब लोग पीछे रह जायेंगे ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वाइफरकैशन हो भी गया, तो ऐसी हालत में क्या हाऊस को यकीन दिलायेंगे कि पोस्टल और आर०एम०एस० को मिलने वाला बोनस, जो कम्बाइन्ड सर्विसेज में मिल रहा है, उस पर कोई इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा और उनकी सर्विसेज और और प्रोमोशन आदि में भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : रिकमेंडेशन्स से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं, तो स्टाफ का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इनको कहना चाहिये कि नारी और साड़ी के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्वामी ही कह सकते हैं ।

श्री आर० एन० राकेश : दूसरा मेरा सवाल यह है कि वैसे तो एनुअल बजट में घाटा पूरा हो जाता है, पोस्टल और आर०एम०एस० की सर्विसेज अलग होने पर भी घाटा कोई खास नहीं रहेगा और अगर घाटा आता भी है, तो जैसे एजूकेशन और होस्पीटल में अगर कामर्शियल प्वाइन्ट आफ व्यू को सरकार देखे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, इसी तरह से इसमें भी इस चीज को देखना चाहिये। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि अगर पोस्टल और आर०एम०एस० तार और टेलीफोन से अलग होगा, तो इसका इफेक्ट पोस्ट कार्ड पर, लिफाफे पर और इन्लैंड लिफाफे पर तो नहीं पड़ेगा और उनके दाम तो नहीं बढ़ेंगे ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आज भी पोस्टल साइड काफी लाभ उठा रही है और सरकार उसको पब्लिक यूटीलिटी सर्विस के नाते चला रही है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा ।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में एडमिट किया है कि सरीन कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने के फार-रीचिंग कांसीक्युंसेज होंगे । मिसाल के तौर पर अगर पोस्टल और आर० एम० एस० को टेलीफोन से अलग कर दिया जाएगा और टेली-कम्युनिकेशन अलग होगा, तो नौबत यह आएगी कि पोस्टल और आर०एम०एस० में आप घाटा दिखायेंगे और फिर आप कहेंगे कि पोस्ट कार्ड के दाम बढ़ाओ और घाटा पूरा करो । ऐसी सूरत को ध्यान में रखते हुए क्या इस समिति की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने से पहले, आप इसको हाऊस में डिस्कस करेंगे । सरीन कमेटी की रिपोर्ट में केवल यही एक इशू नहीं है, बल्कि उसकी और बहुत सारी रिकमेंडेशन हैं । उन सब को इम्पलीमेंट करने से पहले हाऊस में ये इशू डिस्कस हो जायें ताकि पी० एण्ड टी० के घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं, उस पर यहां सुझाव दिये जा सकें और पब्लिक पर कोई बर्डन पड़ने से पहले यहां इस पर डिस्कशन हो जायें । मैं यही कहना चाहूंगा कि हाऊस में इस पर डिस्कशन हो जाये ।

संचार मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं कोई कमिटमेंट तो करना नहीं चाहता . . .

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं करना चाहते ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : क्यों नहीं करना चाहता , यही मैं बता रहा हूं लेकिन सरीन कमेटी की जो रिकमेन्डेशन हैं, वे सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है । जब जो फैसला होगा, उस फैसले को हम जरूर आपको बतायेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, सरीन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में और खास तौर पर टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज को अलग-अलग करने के बारे में आपका कहना है कि रिकगनाइज्ड फेडरेशन्स ने सिद्धांत रूप में कोई विरोध नहीं किया है । अब इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने बड़े इशू पर क्या आप यह मुनासिब नहीं समझते कि तमाम रिकगनाइज्ड फेडरेशन्स से डिस्कशन करके आप किसी एक नतीजे पर पहुंचें ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहले भी इस मामले में जो यूनियन्स हैं, उनके साथ डिस्कस किया है और जहां-जहां जरूरत महसूस होती है, उनसे डिस्कस करते हैं और उनके विचार आ भी गये हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : दोनों सर्विसेज को अलग किया है, उस पर ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इससे पहले यूनियन्स से बातचीत की है ।

Creation of Additional Power Generating Capacity

*25. SHRI K. RAMAMURTHY:
SHRI R. L. BHATIA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the steps being taken to accelerate the creation of additional power generating capacity in view of the fact that in 1980-81 and in 1981-82 the shortfall in achievement was about 32 per cent;

(b) the steps that have been taken to eliminate the management deficiencies in the State Electricity Boards; and

(c) details of plans that have been formulated to commission 16000 MW in the remaining period of the Sixth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c). The total addition of power generation capacity planned for the Sixth Five Year Plan was 19,66 MW The achievement in 1980-81 has been 1823 M.W. In the second yead 1981-82, the achievemnt has been 2,175 MW. An additon of about 3,500 MW is scheduled during 1982-83. It is ancicipated that the total addition of new generating capacity during the Sixth Plan will be of the order of 14,00 M.W.

In order to speed up the completion of the various power projects, various steps have been taken up by the Govt. With a view to remove bottlenecks, the monitoring of the projects has been considerably stepped up. Construction monitoring directorates have been set up in the Central Electricity Authority to closely monitor the various activities of the projects. Coordination and review meetings are regularly held in the CEA with the Project Authorities equipment suppliers and manufacturers, construction agencies etc. A close watch is kept on all constraints for corrective action. CEA's senior officers visit project sites and take up the matter with the appropriate authorities for removing the bottlenecks. Review meetings are also held in the Department of Power for appropriate action with the State Government as well as the level of the Union Government. Meetings with the Power Ministers of States are also taken by the Minister of Energy at which the commissioning of ongoing power projects is reviewed for taking remedial action.

For improving the management at the project level, detailed guidelines have been issued to the State Electricity Boards in July, 1980. These guidelines inter alia include various networks and formats for keeping all the activities of the projects under a close watch.

For effective coordination and timely receipt of equipments and materials and for availability of the require inputs from the project authorities, a system of harmonograms has been introduced from last year. The future commissioning programme will be coordinated by the project authorities according to these harmonograms.

Lastly, lack of smooth flow of funds to State Electricity Boards is (emerging as a major factor) also delaying implementaion of projects.

SHRI K. RAMAMURTHY: Mr. Speaker, Sir, the target of Sixth Five Year Plan or the additional creation of energy was envisaged at 19,666 M.W. Even in the reply which the hon. Minister has given he agrees that during the Sixth Plan period, it will be of the order of 14,000 M.W. So, the rest of the 5,000 and odd M.W. will not be achieved during the Sixth Five Year Plan. So, I would like to know whether the target of the Sixth Five Year Plan will be achieved hundred per cent or it will be brought down to 14,000 M.W. only.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: Sir, it is true that there are slippages. But, these